RE. QUESTION OF PRIVILEGE AGAINST D.N.A. AND TEHELKA

विपक्ष के नेता (श्री गुलाम नबी आज़ाद): डिप्टी चेयरमैन सर, मैं रूल 190 के तहत बोल रहा हूं।

†قائد حزب اختلاف (جناب غلام نبی آزاد) : ڈپٹی چیئرمین سر، میں رول 190 کے تحت بول رہا ہوں۔

It is the third paragraph of Rule 190 which is about the mode of raising a question of privilege. It is given at page No.66.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Which Rule is it?

SHRI GHULAM NABI AZAD: It is Rule 190 wherein it is required to be taken up immediately after the questions that means the Question Hour since this is the first item of the agenda.

सर, आज सुबह हमारे एक नॉमिनेटेड मेम्बर ने यह इश्यू उठाया था, लेकिन उस वक्त शायद दूसरा आइटम लेना था, इसलिए आपने बताया कि आपने गलत नोटिस दिया है।

سر، آج صبح ہمارے ایک نومینیٹڈ ممبر نے یہ ایشو اٹھایا تھا، لیکن اس وقت شاید دوسرا آئٹم لینا تھا، اس لئے آپ نے بتایا کہ آپ نے غلط نوٹس دیا ہے۔

श्री उपसभापति: उनका सब्जेक्ट अलग था, इसलिए मैंने ऐसा कहा था।

श्री गुलाम नबी आज़ाद: मैं इस रूल के तहत उसी को कह रहा हूं, क्योंकि मैं भी सिग्नेट्री हूं और तकरीबन 60 लोग across the party lines, इस प्रिविलेज मोशन के सिग्नेट्रीज़ हैं। इसलिए, as one of the signatories to it, मैं इस चीज़ को उठा रहा हूं कि इस साल के 6 अप्रैल और 8 अप्रैल को 'डीएनए' और 'तहलका' में यह छपा कि राज्य सभा का जो टेलीविज़न है, उसमें 2010 से लेकर 2014 तक 1,700 करोड़ रुपये खर्च हुए, जबकि सच यह है कि 1,700 करोड़ रुपये खर्च नहीं हुए हैं, सिर्फ 146 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। 146 करोड़ रुपये और 1,700 करोड़ रुपये में तो ज़मीन-आसमान का फर्क है। उन्हीं पेपर्स में यह भी लिखा गया है कि सीएजी ने राज्य सभा टेलीविज़न की वर्किंग और फंक्शनिंग को क्रिटिसाइज़ किया है, जबकि सीएजी की ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। उन्हीं पेपर्स में यह भी कहा गया है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने राज्य सभा टेलीविज़न के खिलाफ कोई नोट सर्कुलेट किया है, जबकि ऐसा कोई नोट नहीं है। फिर relevance of television बताया है राज्य सभा के लिए। That becomes the privilege of the House. सर, यह निर्णय न तो आपने लिया है, न मैंने लिया है, न बीजेपी के किसी एक लीडर ने लिया है, न समाजवादी पार्टी, बीएसपी, जेडीयू के किसी लीडर ने लिया है, बल्कि General Purposes Committee, जिसको माननीय सभापति चेयर करते हैं और जिसमें राइट, लेफ्ट एंड सेंटर, सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स मेम्बर्स हैं, उसने यह फैसला लिया है। इसका मतलब है कि पूरी राज्य सभा ने irrespective of their political affiliation, यह निर्णय लिया है। इसके बारे में, the very relevance of Rajya Sabha TV, यह प्रिविलेज पूरे हाउस का बनता है और यही कारण है कि सभी पार्टीज़ के एक या दो मेम्बर्स ने नहीं, बल्कि 60 मेम्बर्स ने प्रिविलेज मोशन का नोटिस दिया है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूँगा कि इस प्रिविलेज मोशन को एंटरटेन किया जाए और इस पर कार्यवाई की जाए।

---

† Transliteration in Urdu Script.

†جناب غلام نبی آزاد : میں اس رول کے تحت اسی کو کہہ رہا ہوں، کیوں کہ میں بھی سگنیٹری ہوں اور تقریبا 60 لوگ across the party lines, اس پریویلیج موشن کے سگنیٹریز ہیں۔ اس لئے، as one of the signatories to it, میں اس چیز کو اٹھا رہا ہوں کہ اس سال کے 6 اپریل اور 8 اپریل کو 'ڈی۔این۔اے' اور 'تہلکہ' میں یہ چھپا کہ راجیہ سبھا کا جو ٹیلی ویژن ہے، اس میں 2010 سے لیکر 2014 تک 1700 کروڑ روپے خرچ ہوئے، جبکہ سچ یہ ہے کہ 1700 کروڑ روپے خرچ نہیں ہوئے، صرف 146 کروڑ روپے خرچ ہوئے ہیں۔ 146 کروڑ روپے اور 1700 کروڑ میں تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ انہیں پیپرس میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ سی۔اے۔جی۔ نے راجیہ سبھا ٹیلی ویژن کی ورکنگ اور فنکشننگ کو کریٹسائز کیا ہے، جبکہ سی۔اے۔جی۔ کی ایسی کوئی رپورٹ نہیں ہے۔ انہیں پیپرس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ فائنینس منسٹری نے راجیہ سبھا ٹیلی ویژن کے خلاف کوئی نوٹ سرکلیٹ کیا ہے، جبکہ ایسا کوئی نوٹ نہیں ہے۔ پھر relevance of television بتایا ہے راجیہ سبھا کے لئے۔ That becomes the privilege of the House. سر، یہ فیصلہ نہ تو آپ نے لیا ہے، نہ میں نے لیا، نہ بی جے پی کے کسی ایک لیڈر نے لیا ہے، نہ سماجوادی پارٹی، بی۔ایس۔پی۔، جے۔ڈی۔(یو) کے کسی لیڈر نے لیا ہے، بلکہ General Purposes Committee, جس کو مانئے سبھا پتی چیئر کرتے ہیں اور جس میں رائٹ، لیفٹ اینڈ سینٹر، سبھی پالیٹکل پارٹیز کے لیڈر ممبرس ہیں، اس نے یہ فیصلہ لیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پوری راجیہ سبھا نے irrespective of their political affiliation, یہ فیصلہ لیا ہے۔ اس کے بارے میں the very relevance of Rajya Sabha TV, یہ پریویلیج پورے ہاؤس کا بنتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ سبھی پارٹیز کے ایک یا دو ممبرس نے نہیں، بلکہ 60 ممبرس نے پریویلیج موشن کا نوٹس دیا ہے۔ اس لئے میں آپ سے نویدن کروں گا کہ اس پریویلیج موشن کو ایڈمٹ کیا جائے اور اس پر کاروائی کی جائے۔

(ختم شد)

श्री उपसभापति: क्या आपने नोटिस दिया है? Have you given the notice?

SHRI GHULAM NABI AZAD: Yes, Sir.

श्री शरद यादव (बिहार): सर, मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए विरोधी दल के माननीय नेता की बात से संपूर्ण तौर पर सहमत होता हूं। श्रीमन्, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस 1,700 करोड़ रुपये के खर्च के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं है। इस देश में यह सदन इस देश के सवा सौ करोड़ लोगों की धरोहर है। सभापति जी की चेयरमैनशिप में यहां जीपीसी बनी हुई है। फिर उन्होंने फाइनेन्स मिनिस्ट्री का कहा, कुछ नहीं।

महोदय, मैं यहां यह निवेदन कर दूं कि इस देश में मीडिया की आजादी के लिए तो ऐसा है कि मीडिया की आजादी के बगैर देश नहीं चल सकता, दुनिया नहीं चल सकती। लोकतंत्र का यह एक एक बाजू है, एक बड़ी ताकत है। आज देश में यदि कोई जगह है, तो मैं यह कह दूं कि चाहे आर्ट हो, कल्चर हो, संगीत हो, विज्ञान-ज्ञान हो, लोग सभी चैनल्स खंगालते हैं, देखते हैं, ऊब जाते हैं, तो सिर्फ राज्य सभा टेलीविजन की ओर आते हैं। यह एक ऐसी जगह है, जहां से पूरे देश को पूरा सच तो नहीं, दूर तक सच दिखाने का काम होता है। पार्लियामेंटरी मिनिस्टर साहब बैठे हैं, मैं यह मानता हूं कि इस विषय से गंभीर कोई सवाल नहीं है। देश में हजारों चैनल चल रहे हैं, अच्छे शो भी दिखाते हैं, खबरों को भी दिखाते हैं, लेकिन एक बात जो मैं महसूस करता हूं कि हम ही नहीं, देश में अगर आज सबसे ज्यादा कुछ देखा जा रहा है, तो यह राज्य सभा का जो प्रसारण है, इसी को देखा जा रहा है। यहां बहस जिस ताकत के साथ, जिस मजबूती के साथ होती है, उससे सरकार को जरूर दिक्कत होती है,

† Transliteration in Urdu Script.

[श्री शरद यादव]

लेकिन अगर बहस जीवंत न हो, तो लोकशाही और लोकतंत्र के कोई मायने नहीं रहता। तो यह चैनल ऐसा है, यहां का प्रसारण ऐसा है, जो आपकी अगुवाई में है। ...**(समय की घंटी)**... यह सदन ऐसा है, जिस पर हमला होता रहता है। आज ऐसी मर्यादा टूट गई है और बाहर से लोग डिक्टेट तक करते हैं कि यहां किसको एक्सेप्ट करना चाहिए, किसको क्या कर देना चाहिए, इसमें कैसे होना चाहिए, हाउस को क्या करना चाहिए, हम उस पर कभी नहीं बोले। हमारे सदन के लोग भी कभी नहीं बोले, क्योंकि जो हम राजनीतिक लोग हैं, हमारी बरदाश्त की जो शक्ति है, वह ज्यादा है।

श्री उपसभापतिः शरद जी, ठीक है, हो गया।

श्री शरद यादवः आप इसको प्रिविलेज मानेंगे, मान लिया। मैं मानता हूँ कि आपकी न्याय बुद्धि इसे मानेगी। मैं तो इसके मायने को रखना चाहता हूँ कि यह खबरों को देने वाला एक ऐसा अकेला ठिकाना है। इस सदन के बाहर जो यह राज्य सभा टेलीविजन संस्था है, उसके सीईओ, सीएजी से लेकर सबके लिए असत्य छप जाए या कोई ऐसी चीज छप जाए और इसे हमारे आसपास डाल दिया जाए।

श्री उपसभापतिः ठीक है, शरद जी।

श्री शरद यादवः इसलिए इसको तत्काल स्वीकार करके इस पर बहस भी होनी चाहिए और जिन लोगों ने ऐसा किया है, उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। बाकी बाद में रहे, क्योंकि मर्यादा हमारे लिए भी है और मर्यादा लोगों के लिए भी है। वेंकैया जी, यहां बैठे हैं, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। बहुत-बहुत शुक्रिया।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We do not want a discussion on this.

श्री नरेश अग्रवाल (उत्तर प्रदेश)ः उपसभापति जी, हम सिर्फ समर्थन कर रहे हैं, जो नेता विरोधी दल ने कहा और शरद जी ने कहा है। इसमें कहीं न कहीं कोई साजिश नजर आ रही है, क्योंकि इधर लगातार देख रहे हैं कि राज्य सभा का चैनल, राज्य सभा, दोनों पर एक तरीके से साजिश के तहत कुछ न कुछ आक्रमण हो रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस प्रिविलेज मोशन को आप एक्सेप्ट कर लीजिए, प्रिविलेज कमेटी को भेज दीजिए, जिससे सब चीज सही-सही सामने आ जाए।

श्रीमती विप्लव ठाकुर (हिमाचल प्रदेश)ः सर, मुझे भी एक मिनट बोलने दीजिए। ...**(व्यवधान)**..

SHRI D. RAJA (Tamil Nadu): The LOP and other senior colleagues have effectively presented the issue and it is before the Chair. I urge upon the Chair to accept this and decide.

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT; THE MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION; AND THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU) : Mr. Deputy Chairman,

Sir, I have heard the Leader of the Opposition, but I must tell the House that the full facts of the case are not before the House. This is number one.

Number two, when we refer a matter to the Privileges Committee, we must be convinced that there is a privilege involved in this.

Number three, before we admit the motion, we have to be sure of how it is going to affect the image of the House also, *per se*. If there is something written against the House or against a particular individual or a Member of the House, or, if any motives are attributed to the Member of the House or the institutions themselves, then, that is a serious matter. If some comment is made about the utility of the channel, it is a fair criticism. Nobody can have objection to that. I may feel it as very important; others may feel it as not important. Why are you wasting public money? That can be matter of another opinion. That much freedom is there to the people, particularly in the media. So, what I suggest is before you take a decision about the admission of this motion, let us go through the full facts of the case, and then admit it. Otherwise we will be seen as if we are encroaching upon the rights of the media. That is another angle that has to be kept in mind. To be frank, except hearing the Leader of the Opposition, I am not well versed with the full facts. I do not know what is the notice, who are the Members who have given notice and what is the total content of the notice also because that is not circulated to the other Members of the House. Keep all these things in mind before taking a decision. That is my humble suggestion to you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That's all.

SHRI GHULAM NABI AZAD: Before taking a decision, you check up the figures. The facts are there.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We will see all aspects of it. Anyhow, I have got information from the Secretariat that a notice has already been received signed by many Members. Therefore, that notice will be examined and dealt with according to the law.

श्री शरद यादव : माननीय उपसभापति जी, मैं श्री एम. वेंकैया नायडु जी की बात को ठीक मानते हुए, यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस चैनल को सभापति जी हैड करते हैं और इस सदन में हम में से ऐसा कोई नहीं है, जो उनकी मर्यादा को कभी इस सदन में पार करता हो। मैं मानता हूं कि आलोचना हो सकती है, सब कुछ हो सकता है, सारा अधिकार है, लेकिन यह भी ध्यान रखना चाहिए कि लोक सभा के चैनल को वहां स्पीकर देखते हैं और राज्य सभा के टी.वी. चैनल को कोई अकेले सी.ई.ओ. या कोई और नहीं देखता है, बल्कि यह तो केवल सभापति जी के जिम्मे है।

महोदय, इसी सदन ने, यूनेनिमसली हम सब ने मिलकर यह तय किया है कि इसके हैड

[श्री शरद यादव]

सभापति होंगे। इसलिए इसमें सारे तथ्य हैं। इसमें जो एक-दूसरे को जो लिखा गया है, उससे सब विपरीत है। इसलिए मैं यह मानता हूं कि आपको इसे मानना चाहिए और आपको होल हार्टेडली इसका समर्थन करके इसे आगे बढ़ाना चाहिए।

श्री उपसभापतिः शरद जी, रूल के अनुसार देखूंगा। We will examine it in accordance with the rules.

SHRI ANAND SHARMA (Rajasthan): Sir, I am also one of the signatories. We were listening to the Minister of Parliamentary Affairs. There are no two opinions on what he is saying. There is one issue here. There I have slight divergence. The question is utility. Now, this House in its collective wisdom has decided on its utility. How can we expect a fair criticism? Considering the privileges of this House we have our own channel. The other House is having its own channel and that channel is also disseminating information. So, this channel is also doing exactly the same. So, that is where the question of the privilege of this House is involved, when the authority, right and decision of the House to have a dedicated channel is being questioned. That is why we have all signed this petition.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It will be examined according to the rules. We have the Rule Book.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: We are having an enlightened debate. There is nothing wrong. I am not joining issue with either Sharadji or Anand Sharmaji. My only worry is that after all, everything will come up for public scrutiny tomorrow, including comments. Keeping that in mind, one should understand, criticism or a comment on the channel is not a comment on the Chairman. Let that be very clear. Criticism about the contents of the channel's telecast is not a criticism of the House, which has decided, in its collective wisdom, to have a channel of its own. There is nothing wrong with that. We unanimously passed a legislation such as the Judicial Appointments Commission. We hear criticism about that too. So, there is criticism even at that level! So that being the case, we are in a democracy and the Parliament has got its importance and the media also has its importance. So, while taking a decision, keep all these things in mind, particularly the contents, the facts that have been mentioned, or twisted and misrepresented, and then take a considered view. That is what I have said.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is all. All aspects would be looked into and we would deal with it according to the rules in the Rule Book.

SHRI K.T.S. TULSI (Nominated): Sir, more than 60 Members have signed the notice, and they are from most parties. It is not a partisan issue. This is not a question of criticism. This House is in the forefront for defending the freedom of expression. But this is malicious. Contrary to record, nobody was contacted. This is an attempt to malign the entire House. If malicious attempts are allowed...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We will examine that. Now, let us take up a Bill for introduction – The Commercial Courts, Commercial Division and Commercial Appellate Division of High Courts Bill, 2015. Shri D. V. Sadananda Gowda to move.

GOVERNMENT BILLS

The Commercial Courts, Commercial Division and Commercial Appellate Division of High Courts Bill, 2015

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI D. V. SADANANDA GOWDA): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the constitution of Commercial Courts, Commercial Division and Commercial Appellate Division in the High Courts for adjudicating commercial disputes and for matters connected therewith or incidental thereto.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI D. V. SADANANDA GOWDA: Sir, I introduce the Bill.

Sir, I have a small submission to make. On the last occasion, another Bill, the Delhi High Courts (Amendment) Bill, was introduced by me. In the meanwhile, some objections had been raised in this House and they said that The Commercial Courts, Commercial Division and Commercial Appellate Division of High Courts Bill, 2015 and that Bill should be taken together. Now, it is my request that since the Delhi District Bar Associations are going on strike, that Bill needs to be passed at the earliest. My earnest request is, both the Bills may be taken together at the earliest, because this Bill already, right from 2003, has passed through various stages. It has gone to the Standing Committee; it has gone back to the law Commission; it was also passed by the Lok Sabha and then, withdrawn. All these things have happened. So, both these Bills may be taken up together.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. But now you have introduced only this Bill.